

राजस्व (Public Finance)

बजट एवं बजट के सिद्धांत Budget and Principles of Budget

बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द **ब्यूजे (Bougettee)** से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। सन 1733 तक इस शब्द का प्रयोग इंग्लैंड ने **जादू के पिटारे** के रूप में किया जाता।

बजट में देश के आय व व्यय का वितरण आर्थिक आधार पर होता है। जिसे वित्त मंत्री लोक सभा के सम्मुख रखता है। सन 1803 में फ्रांस इस अर्थ में बजट का प्रयोग किया और बाद में विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी इसका इसी अर्थ में प्रयोग किया। फ्रांस में 1779 बजट का उद्भव हुआ और 1871 में यह जर्मन पहुँच गया।

बजट की परिभाषाएं

गैस्टन जेज के अनुसार, “एक आधुनिक राज्य में बजट एक पूर्व कल्पना तथा सार्वजनिक आय एवं व्यय का एक अनुमान है तथा कुछ विशिष्ट व्ययों को करने व आय को प्राप्त करने का अधिकार है”।

पी एल बिल्यू के अनुसार, “यह एक निश्चित अवधि की अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण है, यह तुलनात्मक तालिका है जिसमें प्राप्त होने वाली आय तथा किये जाने वाले व्ययों की राशियों को दिखाया जाता है”।

टेलर के अनुसार, “बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना है। यह आगामी आय के अनुमान तथा बजट के प्रस्तावित व्ययों के अनुमान के साथ-साथ प्रदान करता है”।

इस प्रकार बजट एक ऐसी पारिमाणिक वित्तीय विवरण है जो निश्चित समय से पूर्व बनाया जाता है जिसमें निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु अपनाई गई नीति सम्मिलित रहती है।

अर्थशास्त्र के सभी विषयों एवं कक्षाओं के नोट्स, प्रश्नोत्तर, सैंपल पेपर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विगत वर्षों के प्रश्नपत्र, अभ्यास प्रश्नपत्र (हिंदी या अंग्रेजी माध्यम) के PDF आपको www.theeconomicsguru.com पर मिल जायेंगे।

इसके साथ ही सभी हिंदी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए Free **LIVE CLASS** भी उपलब्ध है, हमारे **YOUTUBE CHANNEL "THE ECONOMICS GURU"** पर। अभी **subscribe** कर लीजिये और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिये अपने दोस्तों के बीच।

किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे सम्पर्क कर सकते हैं, YOUTUBE के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या वेबसाइट के Email वाले Option में जाकर **Email** करे या WhatsApp कर सकते हैं (Website में लिंक दिया गया है।

धन्यवाद

नकुल ढाली

The Economics Guru

लाभार्थी बोर्ड:

CBSE, UK Board, UP Board, Bihar Board, MP Board, CG Board, Rajasthan Board, Haryana Board

साथ ही **BA; B.COM; MA** के सभी **SEMESTER** लिए भी अध्ययन सामग्री उपलब्ध है।



अभी VISIT करें

www.theeconomicsguru.com

Subscribe my **YOUTUBE** channel **THE ECONOMICS GURU**

Follow me:THE ECONOMICS GURU
EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGEFacebook- *Nakul Dhali*Instagram- *@dhalinakul*www.theeconomicsguru.com

एक अच्छे बजट के गुण

एक आदर्श बजट निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए-

- यह एक विवरण के रूप में बनाया जाता है।
- इसे एक निश्चित समय से पूर्व तैयार किया जाता है।
- इसमें भविष्य के लिए प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का वर्णन होता है।
- इसमें वित्त संबंधी ब्योरे दिए जाते हैं।
- राष्ट्रीय क्रियाओं में बजट अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
- बजट इस प्रकार बनाया जाता है कि देश में कर का प्रभाव न्यायपूर्ण हो।
- प्रारंभ में बजट प्रायः घाटे के बनाए जाते हैं, जिससे बाद में संतुलित कर दिया जाता है।
- बजट का निर्माण सदैव नियोजन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

बजट के उद्देश्य

लेख देयता

लोकतंत्र में कोई भी व्यय करारोपण संसद व विधान सभा की अनुमति के बिना संभव नहीं है। आर्थिक बजट प्रणाली बजट वित्त पर विधानमंडल का नियंत्रण रखने का एक सबल माध्यम है। इस बात की व्यवस्था की जाती है कि व्यय हेतु जितनी राशि स्वीकृत हुई है, उससे अधिक राशि व्यय नहीं की जानी चाहिए।

कार्यकलाप बजट पद्धति

बजट प्रस्तावों की रचना का उनके कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाता है। बजट की रचना एवं इसके वास्तविक परिणामों के मध्य मेल स्थापित किया जाता है।

EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

राजकीय नीति का उपकरण

बजट राज्य की नीति का एक प्रधान उपकरण है। अर्थव्यवस्था में वांछित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बजट नीति को निर्धारण किया जाता है। कराधान व सार्वजनिक व्यय के स्तर पर दौरा आर्थिक लक्ष्य विकास तथा संपत्ति के वितरण में समानता को कम किया जाता है।

कार्यात्मक दृष्टिकोण

बजटों में आय तथा व्यय का ऐसा प्रावधान किया गया है जो आर्थिक क्षेत्र में प्रभावशाली परिणाम दे सकें। इससे सरकार के कार्यों को स्पष्ट चित्र जनता के सामने आ जाता।

योजना से संबंधित

आर्थिक विकास के संदर्भ में योजनाओं से संबंधित बजट प्रावधानों को रखा जाता है। लक्ष्य निर्धारण करके उसे प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। लक्ष्यों का निर्धारण योजना के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

नियोजन एवं बजट में अंतर

नियोजन एवं बजट में मुख्य अंतर इस प्रकार है-

नियोजन का आधार- बजट नियोजन अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है और उसी के अनुरूप बजट का निर्माण किया जाता है। इसके विपरीत, नियोजन को बजट के आधार पर समायोजित नहीं किया जाता। बजट पर नियोजन में परिवर्तन करना संभव नहीं होता।

आर्थिक एवं भौतिक दृष्टि योजना का निर्माण आर्थिक एवं भौतिक दोनों ही दृष्टि से किया जाता है, जबकि बजट का निर्माण केवल आर्थिक दृष्टि से किया जाता है।

अवधि बजट के निर्माण प्रयास प्रत्येक अगले वित्तीय वर्ष के लिए किया जाता है अर्थात् बजट की अवधि प्रायः एक वर्ष की होती है, जबकि नियोजन में योजना का निर्माण प्रायः पाँच या सात वर्षों के लिए किया जाता है।

व्यय सीमा बजट में स्वीकृत धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष में व्यय करना आवश्यक होता है, जबकि योजना में व्यय करने संबंधी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी।

आयगत तथा पूंजीगत बजट में आयगत व पूंजीगत दोनों ही मदों को सम्मिलित किया जाता है। जबकि योजना में ऐसा नहीं है।

EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

बजट के महत्त्व

बजट किसी देश की आर्थिक स्थिति का दर्पण होता है। वर्तमान समय में बजट का स्थान महत्वपूर्ण है। बजट एक ऐसा आधार है जिसके बिना देश की सामाजिक तथा राजनीतिक उन्नति संभव नहीं हो पाती। इस प्रकार, बजट के उद्देश्यों को निम्न प्रकार रखा जा सकता है-

- अधिकारियों के कार्यक्षेत्र का निर्धारण
- आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति
- आर्थिक नियंत्रण
- आय व्यय का निर्देशन
- आर्थिक स्थिरता
- सरकारी वित्त के वृहद योजना

बजट सिद्धांत (Principles of Budget)

बजट को प्रशासनिक प्रबंध का उदय माना जाता है। यह समन्वय का एक शक्तिशाली उपकरण एवं क्षय को रोकने का प्रभावी संयंत्र माना जाता है। टेलर के अनुसार, “बजट को सरकार के वित्त की वृहद् योजना कहा जाता है”।

बजट के प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार हैं-

निष्पादन कार्यक्रम-

इस बजट निर्माण होने के बाद सरकार का यह दायित्व होता है कि उसे लागू करें। यह कार्य प्रमुख अधिकारी द्वारा किया जाता है। बजट का कार्यक्रम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो प्रत्यक्ष रूप से मुख्य अधिकारी द्वारा पूरे किए जाते हैं।

निष्पादन उत्तरदायित्व

अधिकारी को यह देखना होता है कि विभागीय कार्यक्रम विधान की शर्तों को पूरा करते हुए कार्यक्रम का निष्पादन करते हैं तथा इसमें मितव्ययिता का प्रयोग किया जाता है।

रिपोर्ट देना कार्य की प्रगति के बारे में सोचना है। कार्यकारिणी एवं वैधानिक शाखा को दी जानी चाहिए, जिसमें व्यय तथा आय आदि की पूरी जानकारी रहने आवश्यक है।

पर्याप्त उपकरण बजट के दायित्व को पूरा करने में मुख्य अधिकारी के पास पर्याप्त प्रशासनिक उपकरण होना आवश्यक है।

बहुमुखी प्रक्रिया

सरकार को अनेक कार्य करने होते हैं तथा बजटों में अनेक प्रकार के कार्य करने का पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। बहुमुखी प्रक्रिया द्वारा ही देश में आर्थिक विकास संभव किया जा सकता है।

निष्पादन निर्देश बजट में संसद के लिये पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा अधिकारी के लिये मार्गदर्शन होना चाहिए। इस प्रकार बजट में निष्पादन निर्देशन का होना आवश्यक माना गया है।

समय में लोच बजट में बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बदलने की लोच होनी चाहिए तथा समय के आधार पर उसमें परिवर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए।

बजट संगठन का द्विमार्गी होना- बजट की सफलता समस्त विभागों की कुशलता एवं सहयोग पर निर्भर करती है। प्रत्येक विभाग में एक बजट कार्यालय होना चाहिए जिससे बजट को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा सके।

वार्षिक संतुलन का बजट

प्राचीन समय में सरकारी व्यय कम होता था तथा सरकारी हस्तक्षेप भी न्यूनतम था। सरकार की आय प्राप्त करने तथा व्यय करने के अधिकार सीमित थे। उस समय बचत के बजट बनाने वाली सरकार अच्छी मानी जाती थी। परन्तु मंदी ने इस विचारधारा को तोड़ दिया। आज घाटे की बजट का युग है।

बजट के प्रकार

आधिक्य बजट

जब सार्वजनिक व्यय की तुलना में आये अधिक हो तो ऐसे बजट को अधिक का बजट कहते हैं।

पूंजीगत बजट

इस बजट में केवल पूंजीगत मुद्दों को ही सम्मिलित किया जाता है। इसके लिए सार्वजनिक ऋण द्वारा ही धन प्राप्त किया जाता है। इसे सामान्य बजट से पृथक रखा जाता है।

रोकड़ बजट

इस बजट में सरकार के समस्त रोकड़ संबंधी आय एवं व्ययों को रखा जाता है। इससे देश की सही आर्थिक स्थिति में ज्ञान प्राप्त होता है।

बहुउद्देशीय बजट

इस बजट का उद्देश्य देश में वित्तीय नियंत्रण रखना एवं वित्तीय योजना को सफल बनाना है। देश में समस्या उत्पन्न होने पर बजट भी सहायता से इसका उचित समाधान दिया जाता है। अतः यह बजट अल्पकालीन होता है।

आपत्तिकालीन बजट

युद्ध एवं मंदी जैसे संकटकालीन परिस्थितियों में साधारण बजट के अतिरिक्त बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप एक और बजट का निर्माण किया जाता है जिसे आपत्तिकालीन बजट कहा जाता है।

साधारण बजट

जो बजट सामान्य परिस्थितियों में वार्षिक आधार पर तैयार किए जाते हैं उन्हें साधारण बजट कहते हैं। इस बजट में सरकार के समस्त क्रियाओं का सही विवरण प्राप्त हो पाता है।

घाटे का बजट

यदि बजट में आय की अपेक्षा को अधिक मात्रा में देखा जाए तो उसे घाटे का बजट कहते हैं। अर्द्ध विकसित देशों में तीव्र आर्थिक विकास हेतु प्रयास घाटे के बजट ही बनाया जाता।

संतुलित बजट

जब बजट अवधि में आयगत प्राप्तियां तथा आयगत व्यय बराबर तो उसने संतुलित बजट कहते हैं। यह एक आदर्श व्यवस्था होती है जिसका पालन करना बड़ा कठिन कार्य होता है।

बजट के लाभ

बजट निर्माण कराने के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं-

- बजट का मितव्ययी होना
- व्यापक बजट
- वास्तविक खोना
- संतुलित बजट
- बजट का कल्याणकारी होना
- प्रभाव से मुक्ति

बजट प्रक्रिया/ बजट बनाने की विधि

(Budget Process)

प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था वाले राष्ट्रों में बजट बनाने में समान विधि प्रयोग में लाई जाती है।

बजट निर्माण विधि को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है।

बजट की तैयारी (Preparation of Budget)

बजट कार्यकारिणी द्वारा को तैयार किया जाता है।

भारत में प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाता है। यह बजट आयगत खाते व पूंजीगत खाते के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

बजट तैयार करने से पूर्व सभी विभागों एवं मंत्रालय को सूचित कर दिया जाता है, जिससे आगामी तीन वर्षों की आय व व्यय के अनुमान मांगे जाते हैं।

इन अनुमानों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

- i. वेतनमान का संबंध वर्तमान से होता है।
- ii. वे अनुमान जिनका संबंध भावी व्यवस्था से होता है।

इन अनुमानों को निश्चित शीर्षकों के अंतर्गत आंकड़े दिए जाते हैं जैसे-

- i. गत वर्ष की आय व व्यय।
- ii. चालू वर्ष की आय एवं व्यय संबंधी आंकड़े।
- iii. चालू वर्ष के शोधित आय एवं व्यय के आंकड़े।
- iv. गत वर्ष के बजट अनुमान।
- v. गत वर्ष व चालू वर्ष के वास्तविक आंकड़े।

बजट अनुमानों को विभागाध्यक्षों के पास भेज दिया जाता है। जो कि इनका सावधानी से अध्ययन करके संपूर्ण विभाग के लिए एक संयुक्त अनुमान तैयार करते हैं और उसके तीन प्रतिया तैयार करके एक प्रति प्रशासन विभाग को दे देते हैं।

विभागों से प्राप्त अनुमानों का प्रशासन विभाग द्वारा निरीक्षण करने और कुछ आवश्यक टिप्पणियों सहित उसे वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाता है जो उनका पूरा निरीक्षण करता है।

बजट का प्रस्तुतीकरण (Presentation of Budget)

बजट तैयार करने के बाद उसे परिषद में प्रस्तुत किया जाता है।

भारत में दोनों सभा में यह बजट प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्री बजट पेश करने में अपना भाषण देता है जिस पर कोई बहस नहीं की जाती है और इसमें वित्तीय प्रस्तावों के कारणों पर प्रकाश डाला जाता है तथा करारोपण में छूट पर भी बताये जाते हैं।

बजट भाषण बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यदि घाटे का बजट है तो इसे पूरा करने के उपाय भी बताए जाते हैं। बजट संतुलन, घाटे का या बचत का हो सकता है, परन्तु वित्त मंत्री को यह बताना होगा कि उसने ऐसा बजट क्यों बनाया?

वित्त मंत्री द्वारा इस प्रकार भाषण में मौखिक प्रश्न एवं वित्तीय स्थितियों पर प्रकाश डाला जाता है।

सामान्य बहस (General Discussion)

वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के बाद दोनों सदनों में सामान्य बहस की जाती है। **वाद-विवाद प्रायः तीन दिन तक रहता है** जिसमें सदस्यों को सरकारी नीति की आलोचना करने के पूरे अधिकार होते हैं। परन्तु *प्रस्ताव रखने या वोट के लिये प्रस्ताव रखने का कोई अधिकार नहीं होता।* यह बहस निश्चित तिथि तक चलता है। उसके बाद वित्त मंत्री उनके उत्तर देता है और बहस समाप्त हुई समझी जाती है। व्यय की प्रत्येक मद को सामान्य बहस में रखा जाना अनिवार्य है।

मतदान (Voting)

बजट पर सामान्य बहस हो जाने की बात विभिन्न विभागों के मंत्री अपने अपने विभाग के लिए अनुमानों की मांग करते हैं। इन पर पृथक पृथक बहस होती है। बजट की समस्त मदों को दो भागों में रखकर विभाजित किया जाता है-

मतदान आयोग्य के मद (Non-Voting Items)

इसमें वे व्यय सम्मिलित किए जाते हैं जिन पर लोकसभा को मतदान करने की आवश्यकता नहीं होती और यह व्यय भारत के संगठित कोष से दिए जाते हैं जो इस प्रकार-

- राष्ट्रपति का वेतन उनके कार्यालय से संबंधित।
- सर्वोच्च न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं उनके वेतन।
- भारत के प्रधान लेखा परीक्षक का वेतन भत्ता।
- ऋण संबंधी व्यय।
- विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का वेतन एवं लोकसभा के प्रवक्ता एवं वक्ता के वेतन।
- संघीय न्यायालय ने न्यायाधीशों के वेतन।
- ऋण संबंधी मूल, धन एवं व्याज।
- न्यायालय के आदेशानुसार सरकार की देनदारी।
- कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा चुकाना आवश्यक हो।

मतदान योग्य मदें (Votable Items)

- इसमें उन मदों को सम्मिलित किया जाता है जिन पर मतदान की आवश्यकता होती है।
- इन मदों पर बहस का समय पृथक पृथक निर्धारित कर दिया जाता है।
- इसमें लोकसभा का मत लेकर उन मांग को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है।
- मांगों पर बहस के लिए अध्यक्ष द्वारा कुछ खास दिन निश्चित कर दिए जाते हैं।
- मांगों पर खुलकर बहस की जाती है और सदन द्वारा स्वीकृत होने पर अनुदान मानी जाती है।
- अनुदान संबंधी मांगों के सभी प्रश्न बताए जाने के बाद उन्हें गिलोटिन कहते हैं।

कटौती प्रस्ताव (Cut Motion)

कटौती प्रस्तावकों दो उद्देश्य होते हैं-

- सरकारी व्यय में मितव्ययिता लाना।
- शासन के अनुमानों के संबंध में विशेष बात की जानकारी प्राप्त करना।

मितव्ययता लाने हेतु बड़ी मात्रा में कटौती प्रस्ताव के संबंध में प्रस्तावक को यह सुझाव स्वयं ही देना पड़ता है कि किस मद में किस प्रकार की कटौती संभव है? इसके विपरीत छोटी सी कटौती को **सांकेतिक कटौती** कहते हैं। उत्तर संतोषप्रद होने पर प्रस्ताव वापस हो जाते हैं। स्वीकृत होने पर सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है, परंतु इस स्थिति में सरकार का पतन होना जरूरी नहीं।

पूरक बजट (Supplementary Budget)

देश में विशेष परिस्थितियाँ होने पर यदि व्यय समय के पूर्व ही समाप्त हो जाता है तो समय के लिए अतिरिक्त राशि की मांग पूरक बजट की सहायता से हो जाती है तथा भारत में यह बजट नवंबर में पेश किया जाता है। पूरक बजट के लिए संसद से स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक माना गया है।

सांकेतिक मांगे (Token Grants)

बजट स्वीकृत होने के बाद कुछ मदे ऐसी होती हैं जिन्हें अनिवार्य रूप से व्यय करना आवश्यक होता है। परन्तु संसद के सामने लाकर स्वीकृति भी प्राप्त करनी होती है तो ऐसी परिस्थिति में सांकेतिक मांग के रूप में इस व्यय को स्वीकृति लेने हेतु सदन में प्रस्तुत किया जाता है।

यदि किसी विशेष कारण से निर्धारित राशि से अधिक धन व्यय हो गया है। तो उसकी स्वीकृति के लिए अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की जाती है। इन अनुदानों की मांगों को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व **सार्वजनिक लेखा समिति** के सम्मुख रखा जाता है।

THE ECONOMICS GURU

EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

विनियोजन विधेयक (The Appropriation Bill)

बजट की मांगों पर बहस हो जाने के बाद एक विनियोजन विधेयक रखा जाता है जिसमें **कर लगाने का सुझाव** होते हैं। इसकी प्रक्रिया साधारण विधेयक के समान होती है। लोक सभा द्वारा अपनी कार्यवाही पूरा कर लेने पर इसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। इसके बाद इस विधेयक को कानूनी रूप मिल जाता है जो सरकार को संचित कोषों से धन निकालने की अनुमति मिल जाती है।

वित्त विधेयक (Finance Bill)

करों के संग्रह के संबंध में वित्त बिल सदन में रखा जाता है। ये बिल पारित होने पर अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। इस विधेयक में समस्त करारोपण संबंधी प्रस्तावों को सम्मिलित किया जाता है।

बजट का निष्पादन (Execution of Budget)

बजट निष्पादन में आय को प्राप्त करके उन्हें बजट के अनुरूप तय किया जाता है। आय प्राप्त करने व व्यय करने संबंधी व्यवस्था निम्नवत है-

आय प्राप्त करना

बजट पास होने के पश्चात कर वसूल करने के दायित्व वित्त मंत्रालय पर होते हैं। इसके अधीन एक केंद्रीय आय बोर्ड होता है जो सरकार के विभिन्न विभागों से करके वसूली करता है। इस बोर्ड के अनेक विभाग होते हैं जैसे- आयकर विभाग, आबकारी विभाग आदि। करो की राशि को बैंक में जमा कर दिया जाता है जिसका हिसाब वसूल करने वाले अधिकारी और प्राप्त करने वाले संस्थाएँ अपने अपने पास रखते। कर वसूली का कार्य राज्य में आगाम विभाग को सौंपा जाता है, जिसका वित्त विभाग से संपर्क बने रहना आवश्यक है।

व्यय करने के ढंग

विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों को उनके द्वारा व्यय होने वाली राशि की सूचना दे दी जाती है।

कोई भी अधिकारी उस समय तक धन व्यय नहीं कर सकता जब तक कि उसे -

- उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त न हो जाए।
 - चालू वर्ष में व्यय करने की व्यवस्था ना कर दी गयी हो।
- प्रत्येक विभाग का व्यय निर्धारित राशि से अधिक नहीं हो सकता है। व्ययों पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र में ऑडिटर जनरल एवं राज्य में लेखापाल रहते हैं। समस्त भुगतान सरकारी खजाने द्वारा रिज़र्व बैंक पर चेक लिखकर किए जाते हैं। बजट भी स्वीकृत राशि से अधिक राशि व नहीं की जा सकती तथा उस राशि को उसी वित्तीय वर्ष में व्यय होना चाहिए अन्यथा बची राशि डूब जाती है और उसे अगले वर्ष के लिए प्राप्त नहीं किया जा सकता।

व्यय की स्वीकृति देने वाले आबकारी अधिकारी दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं।

- मितव्ययिता लाने के प्रयास करना
- बजट में दिए गए नियमों एवं आदेशों के अनुसार व्यय करना।

लेखा अनुदान (Accounts Estimates)

संविधान की धारा 16(1) के अनुसार, "लेखा अनुदान संसद द्वारा पास किया गया एक अग्रिम अनुदान है जो नियमित बजट पास होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए अनुमानित व्यय के संबंध में होता है"। यह उपाय उस समय प्रयोग किया जाता है जब बजट में सामान्य बहस अप्रैल में भी चलती रहती हो।

बजटिंग के लक्षण

बजट बनाने में निर्णय बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है-

नकदी के आधार पर

बजट का निर्माण नकदी की आधार पर किया जाना चाहिए, बही खाते के आधार पर नहीं। इस प्रकार बजट में दिखाए जाने वाली समस्त मदें उसी वित्तीय वर्ष से संबंधित होना चाहिए। बजट में पूर्व वर्षों या आगामी वर्षों के आंकड़े केवल प्रदर्शित किए जाते हैं।

कुल आय आधार

बजट को कुल आय के आधार पर बनाया जाना चाहिए। शुद्ध आय के आधार पर नहीं। बजट में कुल आय को एक स्थान पर तथा एकत्रित करने संबंधित भाइयों को दूसरे स्थान पर दिखाया जाना चाहिए। अर्थात् बजट में आय एवं व्यय को पृथक पृथक दिखाया जाना चाहिए।

संसद का नियंत्रण

शासन विभाग पर संसद का पूरा नियंत्रण बने रहने से उन्हें समस्त प्रकार के व्ययों के लिए संसद से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कोई व्यय सार्वजनिक क्षेत्र में किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

वास्तविक अनुमान

बजट में अनुमानों को वास्तविक आधार पर ही दिखाया जाना चाहिए।
बजट को अनुमानित आधार पर दिखाने से जनता से अधिक मात्रा में कर वसूल कर लिया जाएगा, जो कि उचित नहीं है।

वास्तविक स्थिति

बजट को एक व्यय में एक ही मद में दिखाया जाना चाहिए, जिससे वास्तविक स्थिति को ज्ञात किया जा सके।
यदि अनेक मदों में इसे दिखाया गया तो उसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी।

एक वर्षीय बजट

शासन विभाग के कार्यों पर देखभाल उचित नियंत्रण लगाने के लिए बजट को एक वर्षीय आधार पर ही बनाया जाना चाहिए। जिससे प्रत्येक वर्ष लोकसभा कार्यकारिणी कार्यों का अवलोकन कर सकेंगे।

समस्त क्रियाओं का एक ही बजट

देश में समस्त आर्थिक क्रियाओं के लिए एक ही बजट बनाया जाना चाहिए जिससे देश की आर्थिक स्थिति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो सके।

जैसे भारत में पहले दामोदर घाटी निगम एवं रेलवे के लिए जो पृथक पृथक बजट बनाए जाते थे, वह उचित नहीं था।

EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

संतुलित बजट

बजट सदैव संतुलित ही होना चाहिए।

ब्युहलर के अनुसार, "एक संतुलित बजट में सरकार के विश्वास उत्पन्न होता है तथा आर्थिक अव्यवस्था पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है"।

बजट समाप्ति नियम

बजट में व्यवस्था होनी चाहिए कि यदि वित्तीय वर्ष में किसी भी विभाग द्वारा कोई राशि व्यय न की जा सके तो उसे डूबा समझा जाए और अगले वर्ष के लिए उसे आधिक्य के रूप में जमा नहीं किया जा सकता।

समान लिखें

वित्तीय नियंत्रण में सुविधा रहने की दृष्टि से केंद्र एवं राज्यों में समान आधार पर ही लेखों को रखा जाना चाहिए।

संगठन व कुशल वित्तीय प्रबंधन

बजट एवं सरकार की वित्तीय नीति की सफलता देश की संगठित एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन पर निर्भर करती है।

आर्थिक प्रगति का सूचक

बजट देश की आर्थिक प्रगति का सूचक है। अतः बजट का निर्माण करने में अत्यंत ही सावधानीपूर्वक कार्य किया जाना चाहिए।

अर्थशास्त्र के सभी विषयों एवं कक्षाओं के नोट्स, प्रश्नोत्तर, सैंपल पेपर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विगत वर्षों के प्रश्नपत्र, अभ्यास प्रश्नपत्र (हिंदी या अंग्रेजी माध्यम) के PDF आपको www.theeconomicsguru.com पर मिल जायेंगे।

इसके साथ ही सभी हिंदी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए Free **LIVE CLASS** भी उपलब्ध है, हमारे **YOUTUBE CHANNEL "THE ECONOMICS GURU"** पर। अभी **subscribe** कर लीजिये और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिये अपने दोस्तों के बीच।

किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे सम्पर्क कर सकते हैं, YOUTUBE के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या वेबसाइट के Email वाले Option में जाकर **Email** करे या WhatsApp कर सकते हैं (Website में लिंक दिया गया है।

धन्यवाद

नकुल ढाली

The Economics Guru

लाभार्थी बोर्ड:

CBSE, UK Board, UP Board, Bihar Board, MP Board, CG Board, Rajasthan Board, Haryana Board

साथ ही **BA; B.COM; MA** के सभी SEMESTER लिए भी अध्ययन सामग्री उपलब्ध है।



अभी VISIT करें

www.theeconomicsguru.com

Subscribe my **YOUTUBE** channel **THE ECONOMICS GURU**

Follow me:



THE ECONOMICS GURU
EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

Facebook- *Nakul Dhali*

Instagram- *@dhalinakul*

THE ECONOMICS GURU

EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE